



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2018/माघ 2, 1939

No. 31] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2018/MAGHA 2, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

विषय : चीन जन. गण., जर्मनी और सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी मिथाइल फोर्मेडाइड' (डीएमएफ) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/37/2017-डीजीएडी.—मै. बालाजी एमाइन्स लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता/आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण., जर्मनी और सऊदी अरब (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित डी मिथाइल फोर्मेडाइड' (डीएमएफ) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) संबंधी पाटनरोधी जांच शुरू करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद डी मिथाइल फोर्मेडाइड' (डीएमएफ) है। यह एक रंगहीन, उच्च वायुलिंग पोलर एप्रोटिक विलायक है जिसमें एक विशेष गंध होती है। यह गर्म करने पर और अपने डिस्टिलेशन तापमान रेंज पर स्थिर रहता है और जल, अल्कोहल, ईथर, किटॉस, एस्टर, कार्बन डिसल्फाइड और क्लोरिनेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ मुक्त रूप से मिश्रणीय है।

4. पीयूसी का प्रयोग भेषज विनिर्माण, एक्रिलिक पालीमर्स विनिर्माण और कीटनाशी विनिर्मितियों में विलायक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग डीएमएफ की व्युत्पत्तियों के सिंथेसिस के फीडस्टॉक के रूप में होता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अधीन पीयूसी का एक विशिष्ट एचएस कोड 2921 1110 है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद वर्णन सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

समान वस्तु

6. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं हैं परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

7. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना गया है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन मै. बालाजी एमाइन्स लि. द्वारा दायर किया गया है, जो वर्तमान में भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में 2 उत्पादक थे अर्थात् मै. राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि. और मै. बालाजी एमाइन्स, तथापि मै. आरसीएफ ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है। मै. बालाजी एमाइन्स लि. ने संबद्ध देशों से पीयूसी का आयात नहीं किया है और न तो वे संबद्ध देशों में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित हैं या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं।

9. अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता जिसका वर्तमान में कुल घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है, नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

शामिल देश

10. वर्तमान जांच चीन जन. गण., जर्मनी और सऊदी अरब (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

11. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और उसका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाए। याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का दावा भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया है जिसे यह कहते हुए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है कि इस स्तर पर बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत उपलब्ध नहीं है।

12. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके जर्मनी और सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन भी किया है कि उन्हें न तो प्रकाशित स्रोतों से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुआ और नही उक्त देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई।

13. अतः प्राधिकारी ने इस जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य कच्ची सामग्री की कीमतों और घरेलू उद्योग के खपत मानकों, परिवर्तन लागत के अनुमानों, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के आधार पर परिकलित किया है।

निर्यात कीमत

14. याचिकाकर्ता ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयात के मूल्य और मात्रा का आकलन करने के लिए निर्यात कीमत गौण स्रोत अर्थात् एक्सपोर्ट जिनियस से आयात आकड़ों का प्रयोग करके निर्धारित की है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, डी/ओ प्रभारों, प्रहस्तन और निकासी प्रभारों जिन्हें जांचशुरूआत के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया गया था, के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया था। प्राधिकारी जांच की प्रक्रिया के दौरान डीजीसीआईएंडएस से आकड़ों की मांग करेंगे। इसके अलावा प्राधिकारी यदि निर्यातक के आकड़े प्रस्तुत और सत्यापित होते हैं तो विश्वास करना चाहेंगे।

पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन के सभी संबद्ध देशों से निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

16. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठायी जा रही 'क्षति' के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

17. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जाँच अवधि (जाँच अवधि)

18. याचिकाकर्ता ने जाँच की अवधि (पीओआई) का प्रस्ताव 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितंबर, 2017 तक के लिए किया है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजन से, पिछले 3 वर्षों अर्थात् अप्रैल, 14 से मार्च, 15, अप्रैल, 15 से मार्च, 16, अप्रैल 16 से मार्च, 17 के आंकड़ों तथा जाँच की प्रस्तावित अवधि पर विचार किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001**

20. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

21. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितवद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख).

अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2018

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of 'Di Methyl Formamide' (DMF) originating in or exported from China PR, Germany and Saudi Arabia.

F. No. 6/37/2017-DGAD.—M/s. Balaji Amines Ltd (hereinafter referred to as the petitioner/applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of 'Di Methyl Formamide' (DMF) (hereinafter referred to as the "subject

goods”) originating in or exported from China PR, Germany and Saudi Arabia (hereinafter referred to the “subject countries”).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and ‘injury’ exist to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Product under consideration

3. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Di Methyl Formamide (DMF)”. It is a colorless, high boiling polar aprotic solvent with a characteristic odor. It is stable on heating and under its distillation temperature range and is freely miscible with water, alcohols, ethers, ketones, ester, carbon disulfide and chlorinated and aromatic hydrocarbons.

4. The PUC is used as a solvent in pharmaceuticals manufacturing, Acrylic Polymers manufacturer and pesticides formulations. It is used as a feedstock for synthesis of derivatives of DMF.

5. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The PUC has a specific HS code 2921 1110 under Chapter 29 of Customs Tariff Act, 1975. It is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

Like Article

6. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

7. Petitioner has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject countries. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioner in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

8. The Application has been filed by M/s Balaji Amines Ltd., who is presently the only producer of subject goods in India. As per the information available on record, there were 2 producers in India namely M/s Rashtriya Chemical & Fertilizers Ltd. and M/s Balaji Amines, however, M/s RCF has closed their production. M/s Balaji Amines Ltd. have not imported the PUC from the subject countries and are not related either to any exporter or producer of the PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.

9. The Authority, therefore, determines that the petitioner who presently holds 100% share of total domestic production, constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and also satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Countries involved

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR, Germany and Saudi Arabia (referred to as the “subject countries”).

Normal Value

11. Petitioner has claimed that China should be treated as a non-market economy and normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 of Annexure I of the Rules. The petitioner has claimed normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted; stating that consideration of cost or price in a market economy third countries is not available at this stage.

12. Further, the Petitioner has also constructed the normal value for Germany and Saudi Arabia on the basis of cost of production in India, duly adjusted on the grounds as they were neither able to get any documentary evidence from published sources, nor reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in the said countries.

13. The Authority has, therefore, constructed the normal value for all exporters/producers from subject countries based on raw material prices and consumption norms of the domestic industry, estimates of conversion costs, selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin for the purpose of this initiation.

Export Price

14. The petitioner has determined export price using import data from secondary source, i.e. Export Genius, to assess the volume and value of imports of subject goods in India. Price adjustments have been claimed on account of Ocean freight, Marine insurance, Inland freight, D/O Charges, Handling & clearing charges, which has been accepted for the purpose of initiation. The Authority will call or the data from DGCI&S during the course of investigation. Also the Authority would like to rely on data of exporter in case the same are furnished and verified.

Dumping Margin

15. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margin is estimated to be above de minimis for all the subject countries.

Injury and Causal Link

16. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Initiation of anti-dumping investigations

17. And whereas, Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

18. The period of investigation (POI) is from 1st October 2016 to 30th September 2017. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16, Apr'16-Mar'17 and the period of investigation will be considered.

Submission of Information

19. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Time Limit

21. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

23. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

24. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any 5 such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

25. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

29. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-cooperation

30. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority